

चागोस द्वीप विवाद के समाधान में भारत की मदद चाहता है इंग्लैंड

सन्दर्भ

ब्रिटन के विदेश सचिव ने भारत से उम्मीद जताई है कि वह हिंद महासागर में मौजूद 'चागोस द्वीपसमूह' को लेकर अमेरिका इंग्लैंड और मॉरीशस के बीच जारी विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वदिति हो कि पिछले साल मॉरीशस ने इस मुद्दे को अंतराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी थी।

क्यों है विवाद?

- वर्ष 1965 में मॉरीशस को आज़ाद करने के बाद ब्रिटन ने हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस से अलग कर दिया था। हालाँकि, मॉरीशस आज भी इस द्वीप पर अपना अधिकार जताता है।
- 1966 में अमेरिका ने ब्रिटन से एक समझौता किया था, जिसके तहत अगले 50 वर्षों तक यानी 2016 तक उसे नरिबाध रूप से डिगो गार्सिया पर सैन्य गतिविधियों के संचालन की छूट मलि गई थी। इस समझौते के साथ ही अमेरिका ने ब्रिटन के साथ मलिकर इस द्वीपसमूह पर वायु और नौसैनिक बेड़ा स्थापति कर दिया। ज्ञात हो कि डिगो गार्सिया चागोस द्वीपसमूह का ही एक हस्सा है।
- वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने समुद्री नयिमों के तहत इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वर्ष 2010 में द्वीपसमूह के आसपास ब्रिटन द्वारा बनाया गया समुद्री संरक्षति क्षेत्र (जसिमें डिगो गार्सिया सम्मलिति नही है) इस अभसिमय के तहत ब्रिटन के दायतिवों से तर्कसंगत नही है।

चागोस द्वीपसमूह का भारत के लयि महत्त्व

- हिंद महासागर के बीचोंबीच स्थति डिगो गार्सिया द्वीप का रणनीतिक महत्त्व इसलियि है कयोंकयिह द्वीप अपनी भौगोलिक स्थति और चक्रवातीय क्षेत्र से बाहर है। वदिति हो कि अमेरिका ने डिगो गार्सिया स्थति अपने सैन्य बेड़ों का इस्तेमाल इराक और अफगानस्तान के युद्ध में बहुतायत से कयिा था।
- भारत के लयि डिगो गार्सिया में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी तब खासा सरिदरद साबति हुई थी, जब 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान दुनिया में शीतयुद्ध का माहौल बना हुआ था। उस दौर में अमेरिका अपने हतियों के मददेनज़र खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था। इसी दौर में हमारे देश के रणनीतिकारों में यह राय बनी थी कि डिगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य बेड़ों की उपस्थति भारत से लयि भारी खतरा है।
- ब्रिटन का कहना है कि चागोस द्वीपसमूह का मुद्दा वहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार तय होना चाहयि न कि मॉरीशस या कसी अन्य देश की इच्छा के अनुसार, वही इस मामले में भारत का रुख यह है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाने का नरिणय मॉरीशस सरकार को करना होगा और ब्रिटन इसे सकारात्मक कदम मानता है।